समावेशी विकास के लिए जरूरी है कौशल विकास

–डॉ. संजीव कुमार

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में "कौशल विकास योजना, केवल जेब मे पैसे भरने जैसा नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन में आत्मविश्वास भरना है।" यही आत्मविश्वास आने वाले समय में आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा। आज भारत में बेरोजगार लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संवर्धन के तंत्र को तेजी से पुर्नगठित करने की आवश्यकता है, जो उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ यहां आबादी को अपने जीवन की गुणवत्ता को शानदार बनाने में समर्थ बनाएं। भारत सरकार का लक्ष्य इस मिशन के द्वारा 2022 तक बेरोजगार युवाओं का उनकी रूचि अनुसार कौशल विकास करके रोजगारपरक बनाना है।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता से सम्बन्धित प्रयास अब तक हमारे देश मे बिखरे हुए हैं। विकसित देशों में जहां कुशल कार्यबल का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 60 से 90 प्रतिशत के बीच है। इसके विपरीत भारत के कार्यबल का स्तर औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ 4.69 प्रतिशत के निचले स्तर पर है। आज भारत में बेरोजगार लोगों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संवर्धन के परिस्थितिकी तंत्र को तेजी से पुर्नगठित करने की आवश्यकता है, जो उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ यहां आबादी को अपने जीवन की गुणवत्ता को शानदार बनाने में समर्थ बनाएं।

कौशल एवं ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। कौशल का उच्च–स्तर और बेहतर मानक वाले देश घरेलू एवं अंर्तराष्ट्रीय रोजगार बाजार में चुनौतियों और अवसरों को अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। स्वतंत्रता के 68 वर्ष पश्चात् भारत में पहली बार कौशल को रोजगारपरक वनाने की कोशिश हुई और इसके परिणामस्वरूप कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय का गठन हुआ ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए तथा गरीबी, अशिक्षा, आतंकवाद जैसी समस्याओं का सफलतापूर्वक निदान किया जाए।

भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और ग्रामीण जनता ज्यादातर कृषि–आधारित व्यवसायों पर निर्भर रहती है। असली भारत आज भी ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं पशुपालन जैसे परंपरागत कार्यों में संलग्न है। और गरीबी, अशिक्षा से लगातार संघर्ष करते हुए राष्ट्र के निर्माण में मानव संसाधन के रूप में योगदान कर रहे हैं। आज विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करना है तो इन गांवों में रहने वाली जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके इनका सही मार्गदर्शन करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की शक्ति को युवाओं के रूप में देखा। और अपने कौशल भारत मिशन के उद्घोषणा भाषण में कहा कि भारत की 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत है तो 'युवा भारत' का सपना साकार करने का यह सही वक्त है। इनका उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने हेतु **'कौशल भारत–कुशल भारत'** योजना की शुरूआत भारत सरकार ने विश्व कौशल दिवस 15 जुलाई, 2015 को एक मिशन के रूप में की। भारत सरकार का लक्ष्य इस मिशन के द्वारा 2022 तक बेरोजगार युवाओं का उनकी रूचि अनुसार कौशल विकास करके रोजगारपरक बनाना है।

कौशल विकास के मामले में हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले काफी पीछे है। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौशल विकास 3.5 प्रतिशत है। और 2019 तक भारत को 12 करोड़ कौशल युवाओं की जरूरत होगी। पहले वर्षों में लगभग 24 लाख शहरी व ग्रामीण युवाओं को इस योजना के तहत लाया गया। सरकार का लक्ष्य 2022 तक यह संख्या 40 करोड़ से भी ऊपर ले जाने का है। तथा साथ ही यह भी निर्धारित किया कि देश के अंदर युवाओं को विधिवत कौशल विकास की शिक्षा के लिए कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रत्येक राज्य में की जाएगी।

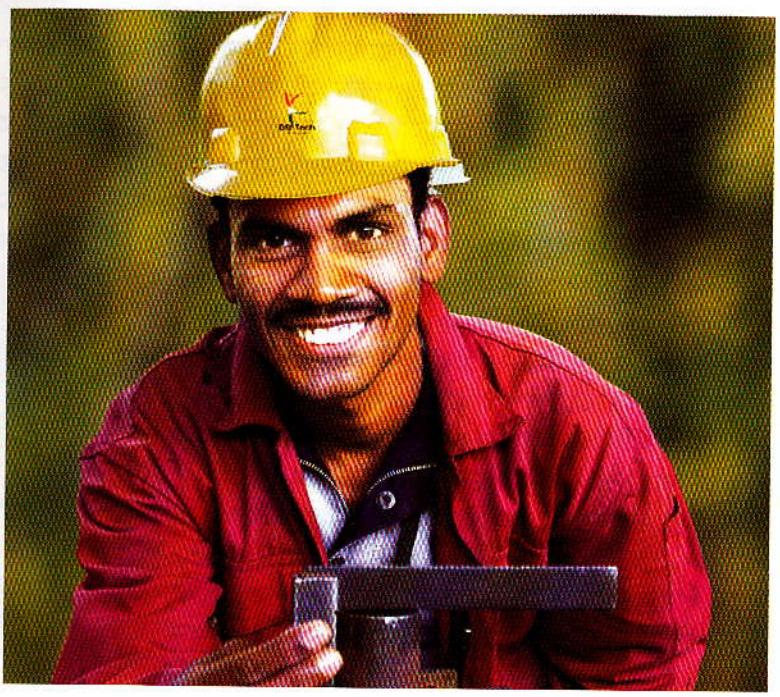

कौशल विकास योजना के उद्देश्य

देश में गरीबी का उन्मूलन कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार दिलाना है। इसके अलावा इस मिशन का उद्देश्य विकास के नए क्षेत्रों को ढूंढ़कर उन्हें विकसित करने का प्रयास करना है। इसके अलावा कौशल विकास योजना के अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. जो गरीब बच्चे उचित शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं उनके अंदर छुपे हुए कौशल को पहचानना है।
2. ज्यादा से ज्यादा युवा शक्ति के हुनर को पहचानना और उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार दिलाना।
3. गरीबी एवं अशिक्षा को दूर करने के अलावा गरीब परिवारों और युवाओं में कौशल विकास करना और उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिलाना।
4. युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ कंप्यूटर शिक्षा देना इस योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक है।
5. भारतीय बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर रोजगारपरक बनाकर राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित करना।
6. कौशल विकास के साथ–साथ उद्यमिता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
7. सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।

भारत में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों?

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत में कौशल विकास योजना कार्यक्रम की शुरुआत रहा। साथ ही केन्द्र सरकार ने एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की। और विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को कौशल विकास योजना के साथ जोड़ा गया जिसमें खासकर ग्रामीण एवं गरीब युवाओं का पूर्ण विकास किया जा सके। भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' एवं 'स्मार्ट सिटीज' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने के अलावा अन्य आवश्यकताएं इसलिए हुई–

1. चीनी आर्थिक विकास दर धीमी होना एक अच्छा अवसर।
2. कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।
3. कौशल पूंजी मे भारत विश्व–स्तर पर गुणवत्ता बनाएं।
4. अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
5. युवा शक्ति को आर्थिक विकास में योगदान के रूप मे स्वीकार करना।
6. भारत को विश्व कौशल की राजधानी बनाना।

कौशल परिवेश की रूपरेखा

विश्व के सबसे बड़े मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत भारत की मानव श्रमशक्ति में प्रत्येक महीने 10 लाख की वृद्धि हो रही है। इसी के आधार पर भारत के कौशल परिवेश के लिए 10 बिंदुओं वाली रूपरेखा तैयार की गई है, जो निम्न है–

1. तेज गति से व्यापक विस्तार एवं प्रसार।
2. गुणवत्तापूर्ण परिणाम पर बल।
3. मानक से जुड़कर कौशल का विकास करना।
4. सभी जातिवर्गों में कौशल विकास पर बल।
5. विश्व में कहीं भी कार्य करने योग्य बनाने का प्रयास।
6. कौशल क्षेत्र के सभी प्रयासों को समेटते हुए उनमें समन्वय स्थापित करना।
7. कुशलता को महत्वाकांक्षा से जोड़ने की पहल।
8. उद्योग जगत से जुड़ाव पर बल।
9. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के बीच अंर्तसंबंध स्थापित।
10. तकनीकी के उपयोग पर बल।

कौशल प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रशिक्षित वृद्धि

कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या सन् 2014 में 1736 थी लेकिन वही 2017 में बढ़कर 8662 तक पहुंच गई यानी 499 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यदि प्रशिक्षण की तुलना करते हैं तो 2014 में प्रशिक्षित लोगों की संख्या 19 लाख 54 हजार 3 सौ थी और 2017 तक यह वृद्धि 600 प्रतिशत पर पहुंच गई। ग्राफ निश्चित करता है कि कौशल विकास योजनाओं से युवाओं के प्रशिक्षण प्रयासों में तेजी आई है।

समावेशी विकास के लिए कौशल विकास

ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास पर बल दे रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडा पर बल दिया गया है। आधुनिक बाजार में भारत के ग्रामीण निर्धनों को आगे लाने में कई चुनौतियां हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा और बाजार के अनुकूल कौशल की कमी होना। विश्व–स्तरीय प्रशिक्षण, वित्तपोषण, रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर देने, रोजगार स्थायी बनाने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने जैसे उपायों के माध्यमों से यह योजना अंतर को पाटने का कार्य करती है।

योजना की विशेषताएं

1. ग्रामीण गरीबों के लिए ग्राम–आधारित निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. समावेशी कार्यक्रम तैयार करना।

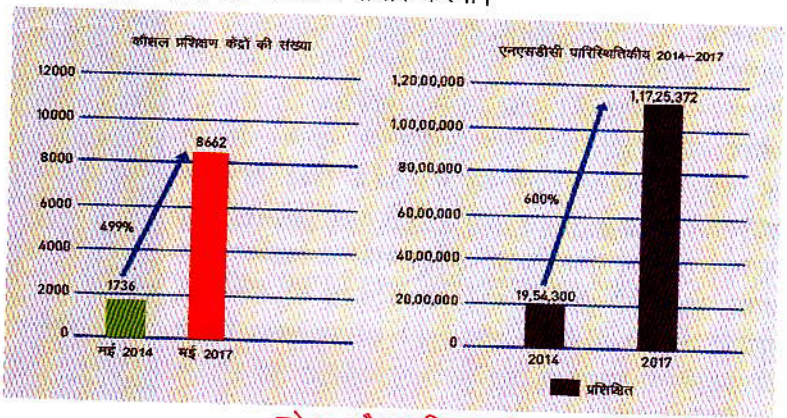

स्रोत– कौशल विकास मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट–2017

3. सामाजिक तौर पर वंचित समूहों (अनु.जाति/जनजाति 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, महिलाएं 33 प्रतिशत) को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया।
4. प्रशिक्षण से लेकर आजीविका उन्नयन पर जोर देना।
5. नियोजन पश्चात् सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व छात्र नेटवर्क तैयार।
6. रोजगार साझेदारी तैयार करने की दिशा में सकारात्मक पहल।
7. कम से कम 75 प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी।
8. जम्मू एवं कश्मीर (हिमायत) पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों (रोशनी) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर।

विभिन्न मंत्रालयों की कुछ प्रमुख योजनाएं।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना; अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग स्कीम; क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम; कौशल विकास प्रयास

ग्रामीण विकास मंत्रालय

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना
- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

कपड़ा मंत्रालय

- इंटीग्रेटिड कौशल विकास नीति

कृषि मंत्रालय

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
- कृषि चिकित्सालय एवं कृषि व्यापार केन्द्र स्कीम
- विस्तार से सुधार क्षेत्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय

- उद्यमिता विकास कार्यक्रम
- उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
- प्रबंधन विकास कार्यक्रम
- प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता स्कीम
- स्किल अपग्रेडेशन एवं क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड वुमैन कोर प्लान

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- अप्रेन्टिसशिप स्कीम
- वोकेशनालाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन
- समुदाय विकास कार्यक्रम पालीटेक्निक द्वारा

सूचना एवं संचार मंत्रालय

- स्टेट फार स्किल डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग
- स्किल डेवलपमेंट इन ई.एस.डी.एम. फार डिजिटल इंडिया

कौशल भारत–कुशल भारत के लाभ

कौशल भारत मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार ने गरीब व वंचित युवाओं को प्रशिक्षित करके बेरोजगारी की समस्या एवं गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा। इस मिशन का उद्देश्य उचित प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास को लाना है जिससे उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के माध्यम से सरकारी, निजी और गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ शैक्षिक संस्थाएं सम्मिलित होकर कार्य करेंगी। कौशल विकास योजना के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं–

1. युवाओं को प्रशिक्षित करना ताकि भारत में बेरोजगारी की समस्या से निपटने में मदद मिले।
2. उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।
3. भारत सें गरीबी खत्म करने में सहायक हो।
4. भारतीयों में छिपी हुई कौशल योग्यता को बढ़ावा देने में सहायक हो।
5. राष्ट्रीय उत्पादन आय के साथ–साथ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके।
6. ग्रामीण गरीब लोगों की जीवन निर्वाह आय में वृद्धि।
7. भारतीयों की जीवन गुणवत्ता में सुधार।

कौशल विकास पर सुझाव

ग्रामीण भारत में कौशल विकास मिशन सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है इससे राष्ट्र का निर्माण एक विकसित, व्यवस्थित रूप से किया जा सकेगा। सरकार की नीतियों में युवाओं के विकास का उद्देश्य अच्छा है लेकिन बहुत–सी कमियां भी हैं। इनको संतुलित करना भी विकास के लिए आवश्यक है। इसके लिए निम्न सुझाव हैं–

1. कौशल विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को बनाए रखा जाए।
2. जो व्यवस्था है उसकी क्षमता के सभी को बराबर अवसर दिए जाएं।
3. स्कूली शिक्षा एवं कौशल विकास प्रयास के लिए सही संतुलन बनाए रखा जाए।
4. कौशल विकास योजनाओं के शोध एवं विकास के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए।
5. परीक्षा, प्रमाणपत्रों एवं उनकी सम्बद्धता की गुणवत्ता बनाई रखी जाए।

निष्कर्ष

भारत में युवाओं की संख्या दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा है। यहां मानव संसाधनों के स्रोत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिससे युवाओं में कौशल विकास के बल पर विश्व–स्तर पर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जा सकता है। ग्रामीण–स्तर पर बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या सबसे ज्यादा बनी हुई है। लेकिन इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होंगे जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के शब्दों में "कौशल विकास योजना, केवल जेब मे पैसे भरने जैसा नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन में आत्मविश्वास भरना है।" यही आत्मविश्वास आने वाले समय में आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा।

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रोफेसर है। तथा इनके कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर एवं पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।)

ई–मेल : sanjeevss786@gmail.com